

कार्यालय परियोजना संचालक, बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर (म0प्र0)

Email ID pdbinapmu@gmail.com

पत्र क्र. 227/बीना पी.एम.यू./बंडा/2020-21
प्रति,

सागर दिनांक 11/02/2021

कलेक्टर महोदय
सागर
जिला-सागर (म.प्र.)

विषय:- संभाग की प्रस्तावित बण्डा वृहद सिंचाई परियोजना से प्रभावित वनभूमि के प्रयोग हेतु पुनरीक्षित F.R.A. Certificate जारी करने बावत्।

संदर्भ:- कलेक्टर सागर का पत्र क्र. 1387 दिनांक 10.10.2018

-----00-----

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग भोपाल द्वारा बण्डा वृहद सिंचाई परियोजना सागर जिले बण्डा तहसील के ग्राम उल्दन के समीप धसान नदी पर प्रस्तावित की गई है। जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)/363/2018/एमपीएस/31/1110/भोपाल दिनांक 26.06.2018 द्वारा ली जा चुकी है। परियोजना का बांध स्थल जिला मुख्यालय से 50 कि.मी. दूरी पर अक्षांश 24°4.35'11" तथा देशांश 78°45'43" पर स्थित है। योजना की अनुमानित लागत रु. 2610.54 करोड़ है। तथा इससे लाभान्वित 333 ग्रामों की 80,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई पहुंचाना प्रस्तावित है। योजना में बण्डा वन परिक्षेत्र की पूर्व में 505.50 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही थी। परन्तु भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा पत्र दिनांक 29.01.2021 के माध्यम 530.85 हेक्टेयर वनभूमि डूब क्षेत्र, डेमशीट एवं पहुंच मार्ग में प्रभावित होना लेख किया है

अतः वनभूमि व्यपर्तन के प्रकरणों में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत अधिकारों के विनिश्चयन की स्थिति प्रमाणित करने हेतु पुनरीक्षित F.R.A. Certificate प्रारूप में जारी किये जाने का अनुरोध है, ताकि वनभूमि के उपयोग के लिये समय पर भारत सरकार को पुनः आवेदन प्रस्तुत किया जा सके।

सहपत्र:- संदर्भितानुसार पत्र

(एच.जी. कुम्हार)
परियोजना प्रबंधक
बीना पी. एम. यू. जल संसाधन
विभाग सागर (म.प्र.)

पृ क्र. 227(4)/बीना पी.एम.यू./बंडा/2020-21

सागर दिनांक 11/02/2021

प्रतिलिपि :-

1. परियोजना संचालक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. अतिरिक्त परियोजना संचालक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर की सूचनार्थ संप्रेषित।

सहपत्र:- शून्य

(एच.जी. कुम्हार)
परियोजना प्रबंधक
बीना पी. एम. यू. जल संसाधन
विभाग सागर (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (जनजाति कार्य विभाग) जिला सागर
क्रमांक/आ0वि0/वनअधि/2018/ 1387 सागर, दिनांक 10/10/2018
प्रति,

परियोजना प्रबंधक,
परियोजना प्रबंधन इकाई बीना
जिला सागर

विषय :- बण्डा वृहद परियोजना हेतु वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत एफआरए
प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने विषयक।
संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक क्यू 1/18/प.प्र/बीना तकनीकी दिनांक 14.3.2018

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा बण्डा वृहद परियोजना
के निर्माण हेतु वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है। उक्त
एफआरए प्रमाण पत्र ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव एवं उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति
मालथौन, के अनुषांसा उपरांत जारी किया गया है। अतएव बण्डा वृहद परियोजना हेतु
एफआरए प्रमाण पत्र (एनेक्चर एक एवं दो) में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- एफआरए प्रमाण पत्र (एनेक्चर 1 एवं 2)

पृष्ठ/आ0वि0/वनअधि/2018/
प्रतिलिपि :-

अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा/मालथौन की ओर सूचनार्थ
प्रेषित।

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग सागर
सागर, दिनांक / /2018

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग सागर

FORM-I

(for linear projects)

Government of Madhya Pradesh
Office of the District Collector Sagar

No. 1387

Dated 10-10-18

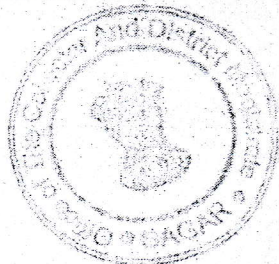
TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter No 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA, for Short) on the Revinew land proposed to be diverted for non forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 505.50 hectares of forest land proposed to be diverted in favour Project Director, Project unit Bina (Name of user agency) for Construction of Banda Brahat Pariyojna (purpose for diversion of forest land) in Sagar District falls within jurisdiction of Gram Panchayat Dahkuli, Kotiya, Kulla, Bahrol, Saliya khurd, Kirola, Uldan, Pidaru, Aratila, Semraata, Pitholi, Imaliya Khurd, Netna, Pehrgua Village(s) in Banda & Malthone tehsils.

It is further certified that :-

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 505.50 hectares of Revinew area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s); Gram Sabha(s); Sub Division Level Committee(s) and the District level Committee are enclosed as annexure-I to annexure 6.
- The diversion of Revinew land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above.



(Signature)
(Alok Kumar Singh)
Collector
Sagar (M.P.)

Collector
Sagar (M.P.)

FORM - II

(For projects other than linear projects)

Government of Madhya Pradesh

Office of the District Collector Sagar

No.....1347

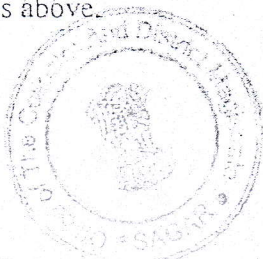
Dated...10.10.12

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the Revinew land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that that **505.50 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour **Project Director, Project unit Bina** (Name of user agency) for Construction of **Banda Brahat Pariyojna** (purpose for diversion of forest land) in Sagar District falls within jurisdiction of Gram Panchayat **Dahkuli, Kotiya, Kulla, Bahrol, Saliya khurd, Kirola, Uldan, Pidarua, Atatila, Semraata, Pitholi, Imaliya Khurd, Netna, Pehrgua Village(s)** in Banda & Malthone tehsils. It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under FRA has been carried out for the entire **505.50 hectares** of Revinew area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(S), Gram Sabha(S), Sub-Division Level Committee(S) and the District level Committee are enclosed as annexure-I to annexure-6
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.
- (c) The each concerned Gram sabha (s) has certified that all formalities /processes under the FRA have been carried out and the they have given their consent to proposed division and compensation and ameliorative measures, if any having understood the purposed and details of proposed division, A copy of certificate issued by the Gram Sabha of Dahkuli, Kotiya, Kulla, Bahrol, Saliya khurd, Kirola, Uldan, Pidarua, Atatila, Semraata, Pitholi, Imaliya Khurd, Netna, Pehrgua villages (s) in enclosed as Annexure-I to annexure-6
- (d) The discussion and decision of such proposal had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of member of Grama sabha present;
- (e) The diversion of Revinew land for facilities managed by the Government as required under section3 (2) of the FRA have been completed and Gram Sabhas have given their consent to it;
- (f) The right of primitive Tribal Ground and Pre Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section3 (1) (e) of the FRA.

Encl.: As above



Alok
(Alok Kumar Singh)
Collector
Sagar (M.P.)
Collector
SAGAR (M. P.)

गण्डा वृहद परियोजना हेतु प्रभावित वन भूमि का वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अधिकारों के विनिश्चय की कार्यवाही हेतु उपखंडस्तरीय वन अधिकार समिति मालथोन का प्रस्ताव

दिनांक _____ को गण्डा वृहद परियोजना से प्रभावित वन भूमि हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकारों के विनिश्चय की कार्यवाही हेतु उपखंडस्तरीय वन अधिकार समिति मालथोन की बैठक आयोजित की गई। निम्न विवरण अनुसार अधिकारीगण उपस्थित रहे-

- 1 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालथोन
- 2 अनुविभागीय अधिकारी (वन) मालथोन
- 3 परियोजना प्रबंधक, परियोजना प्रबंधन इकाई
- 4 सदस्य सचिव उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति

बैठक में परियोजना प्रबंधक, परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा बताया गया कि घसान नदी पर बनने वाली गण्डा वृहद परियोजना हेतु 506.50 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु जनपद पंचायत गण्डा क्षेत्र के 06 ग्रामों की वनभूमि तथा जनपद वमूराबिनेका, कुल्ल, बहराल, सलैयाखुर्द किराला, उल्दन, अल्दन, इमलियाखुर्द, नेतना, पंचायत मालथोन क्षेत्र के 06 ग्राम अटाटीला, रंगरा, अल्दन, अल्दन, इमलियाखुर्द, नेतना, प्रहरगुवा ग्रामों की वनभूमि प्रभावित हो रही है।

जनपद पंचायत गण्डा अंतर्गत ग्राम पंचायत काठिया में पीएफ 407 अंतर्गत 0.7829 हेक्टेयर ग्राम कोटिया में आरएफ 374 अंतर्गत 2.40 हेक्टेयर, ग्राम कुल्ल में पीएफ 404 अंतर्गत 10.6778 हेक्टेयर ग्राम बहराल में पीएफ 403 अंतर्गत 14.8584 ग्राम पंचायत बहराल के ग्राम बहराल में पीएफ 403 अंतर्गत 23.5310 हेक्टेयर, ग्राम सलैयाखुर्द में पीएफ 194, आरएफ 207, आरएफ 205, आरएफ 206, आरएफ 258 अंतर्गत 326.3200 हेक्टेयर, ग्राम पंचायत उल्दन के ग्राम उल्दन में पीएफ 223 अंतर्गत 23.8000 हेक्टेयर, ग्राम पंचायत अल्दन के ग्राम अल्दन में पीएफ 223 कुल 435.9396 हेक्टेयर तथा जनपद पंचायत मालथोन क्षेत्र के ग्राम अटाटीला में पीएफ 223 पीएफ 407 रंगरा में 3.300 हेक्टेयर ग्राम रंगरा में पीएफ 20.18 हेक्टेयर, ग्राम पिथोली में पीएफ 406 अंतर्गत 1.00 हेक्टेयर ग्राम इमलियाखुर्द में पीएफ 218 अंतर्गत 17.3004 हेक्टेयर, ग्राम नेतना में पीएफ 218 अंतर्गत 2.3500 हेक्टेयर, ग्राम प्रहरगुवा पीएफ 195, पीएफ 218 अंतर्गत 19.4 हेक्टेयर कुल 69.5604 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही है। प्रभावित वनभूमि में वन अधिकार अधिनियम कोई भी अनुसूचित जनजाति का कोई भी व्यक्ति का कोई भी दावा आवेदन जमा नहीं है साथ ही पंचायत में कोई भी व्यक्ति का कोई भी दावा आवेदन जमा नहीं है।

समिति द्वारा जनपद पंचायत मालथोन एवं जनपद पंचायत गण्डा क्षेत्र के ग्राम पंचायतों के प्रस्तावों का अवलोकन किया गया। तदोपरान्त गण्डा वृहद परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु वन व्यपर्वतन हेतु समिति द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रस्तावों के आधार पर उपखंड स्तरीय समिति सागर द्वारा परियोजना के डूब क्षेत्र के वन भूमि प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने की अनुशंसा किये जाने का प्रस्ताव करवाया गया।

परियोजना प्रबंधक
इकाई वीना

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
मालथोन

अनुविभागीय अधिकारी (वन)
मालथोन

सदस्य सचिव
वन अधिकार समिति मालथोन

True Copy